National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.nationaljournals.com
ISSN: 2455-9040
Received: 21-11-2022, Accepted: 07-12-2022, Published: 24-12-2022
Volume 7, Issue 2, 2022, Page No. 50-53

भारतीय जनता पार्टी और भारत की विदेश नीति एक टिप्पणी

डॉ. अनुराग पांडेय
असिस्टेंट प्रोफेसर, दयाल सिंह महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

सारांश
यह पेपर भारत की विदेश नीति प्रणाली की नीति क्षमता के गुणात्मक मूल्यांकन का प्रयास करता है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है और अपने बढ़ते हुए हितों की रक्षा करना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। क्या भारत की विदेश नीति की क्षमता अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार है? क्या भारतीय विदेश नीति समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को नए रूप में ढालकर एक सुलझा हुआ कदम उठा रही है? इन्ही कुछ प्रश्नो का उत्तर समझने के लिए लेख वर्तमान नेतृत्व और नीतियों का आंकलन करता है। प्रस्तुत लेख सन 2014 से अब तक की भारतीय विदेश नीति की व्याख्या करता है और ये जानने का प्रयास करता है के क्या भारत की विदेश नीति राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख रही है?

मूल शब्दः विदेश नीति, भारत–चीन, भारत–पाकिस्तान, बचाव अभियान, रु–यूक्रेन युद्ध, राष्ट्र हित, कूटनीति और नैतिकता।

सन 2014 में लगभग तीन दशकों में पहली बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी एक पार्टी ने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की थी, ये दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है। भाजपा ने अपने दम पर शानदार 282 सीटें जीतीं, जो 1984 के लोकसभा चुनावों के बाद से किसी भी पार्टी द्वारा अपने दम पर जीती गई सीटों की सबसे बड़ी संख्या है।
भाजपा की जीत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि यह विजय असंख्य भ्रष्टाचार, घोटालों, देश की विदेश नीति की विफलता, पुरानी आर्थिक संकट और केंद्र में नीतिगत पक्षाघात की सामान्य भावना की पृष्ठभूमि के खिलाफ आई थी। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार कई मोर्चों पर विफल रही थी, जिससे देश को बदलने और इसे समृद्धि के युग में लाने के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार पूर्णतया विफल रही थी। जिससे नागरिकों के मध्य रोष उत्पन्न हो गया था और सत्ता परिवर्तन के लिए लगभग सभी नागरिक भाजपा के साथ एकजुटता के साथ खड़े थे। [1]
हालाँकि, एक के बाद एक घोटालों के उभरने के बाद भ्रष्टाचार यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का मुख्य आकर्षण बन गया, कांग्रेस दल से जनता का मोहभंग, श्री नरेंद्र मोदी का प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं गुजरात में एक प्रभावशाली रिकॉर्ड इत्यादि तथ्यों ने मतदाताओं को भाजपा की ओर आकर्षित किया और सुशासन, चहुँ विकास के लिए भारतीय मतदाता का विश्वास भाजपा में बढ़ा। एक दशक तक सत्ता से बाहर रहने के बाद सन 2014 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। [2]
सन 2019 के चुनावों में फिर से भाजपा पहले से भी अधिक सीटों के साथ सत्ता में आती है, इन चुनावों में कई दलों ने ये भ्र्म फैलाया के 2014 में मिली जीत यूपीए सरकार की विफलाओं, अक्षमताओं और भ्र्टाचार के फलस्वरूप मिली थी और 2019 का रास्ता आसान नहीं होगा लेकिन भाजपा ने इन सभी मिथकों को तोड़ते हुए 2019 में अपनी जीत के साथ ही ये साबित कर दिया कि सरकार ने गरीबों के लाभ के लिए काम किया, भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार किया, देश में समृद्धि लाई, सांस्कृतिक और सभ्यतागत गौरव को बहाल किया और इसके सुरक्षा तंत्र को बढ़ाया। [3]
केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने शासन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, विशेष रूप से एक नई मजबूत विदेश नीति की रचना करने और अमल में लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी मेहतन करि। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने ष्पुट–निरपेक्ष रुख को दूर करने से लेकर वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान का दावा करने तक, अपने पड़ोसी देशों से आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता प्रदर्शित करने के लिए पश्चिमी धारणाओं के अनुरूप भारतीय राज्य के हितों को प्राथमिकता देते हुए, भारत की विदेश नीति में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया।
हालाँकि, भारत की विदेश नीति हमेशा उतनी गतिशील और जीवंत नहीं रही, जितनी कि मोदी सरकार के अधीन है। आजादी के बाद के कुछ दशकों तक, भारत की विदेश नीति एक आपदा थी, जो एक के बाद एक श्नेहरूवादीश भूलों को अंजाम दे रही थी। उदाहरण के लिए, 1948 में जम्मू–कश्मीर पर हमला करने और कब्जा करने के अपने दुस्साहस के लिए पाकिस्तान को माकूल जवाब नहीं देना, या यूएनएससी की सीट चीन को थाली में परोसना और बाद में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के इरादों को गलत समझना, जो अनिवार्य रूप से 1962 के विनाशकारी युद्ध का कारण बना। [4]
लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में, पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद, भारत की विदेश नीति में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। इसने आतंकवाद के अभिशाप से निपटने के लिए पारंपरिक तरीकों से परे जाने की अपनी इच्छा को प्रदर्शित करने के लिए पूर्व और पश्चिम दोनों में सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक किए। बालाकोट एयरस्ट्राइक के साथ, इसने दुनिया को दिखा दिया है कि यह अब अतीत का भारत नहीं है जो चुपचाप बैठकर अपने घाव चाटेगा, बल्कि यह अपने विरोधियों पर एक तेज आक्रमण और सटीक बदला लेगा। [5]

इसके अतिरिक्त, भारत की विदेश नीति भी अविश्वसनीय रूप से निंदनीय रही है, जिसने यूक्रेन के रूसी आक्रमण से निपटने के लिए अपने नपे–तुले दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से भारत के हितों को सबसे ऊपर रखने में मदद की है। मोदी सरकार के अपने 8 साल पूरे होने के साथ, यहां कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो इस बात को रेखांकित करते हैं कि कैसे भारत की विदेश नीति पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकसित हुई है।

भारत अपने पारंपरिक रूप से आयोजित गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण को त्याग देता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक मुखरता प्रदर्शित करता है, जबकि भारत पारंपरिक रूप से अपने विदेश नीति के दृष्टिकोण में गुट–निरपेक्ष रहा है, 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद, नई दिल्ली ने अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विशेष रूप से एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अपनी भूमिका के प्रति प्रतिबद्धताअधिक मुखरता प्रदर्शित की है। [6]

सख्त गुटनिरपेक्षता की पुरानी रणनीति से हटकर, पीएम मोदी ने महान और मध्यम शक्तियों के साथ अटूट और मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसा करके, पीएम मोदी ने भारत को अत्यधिक प्रभावी विदेश नीति के साथ एक रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में बदल दिया है। इसने मूकदर्शक बनकर रहना बंद कर दिया है और वैश्विक गठजोड़ को बढ़ावा देने और मजबूत करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है जिसने एक ऐसे देश के रूप में अपनी भूमिका को ऊंचा किया है जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। [7]

जैसा कि दुनिया ने खुद को कोरोनोवायरस प्रकोप के संकट में पाया, भारत ने वैक्सीन निर्माण में अपनी ताकत का लाभ उठाया, रिकॉर्ड समय में अपना वैक्सीन विकसित किया और पश्चिमी संगठनों द्वारा विकसित टीकों के निर्माण के लिए अपनी क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया। अपनी विदेशी कूटनीति और मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में, भारत ने दुनिया भर के 100 से अधिक देशों को ब्टप्क–19 टीकों की 65 मिलियन खुराक का निर्यात किया, जिसने इसे ष्दुनिया की फार्मेसीष् का उपनाम दिया। [8]

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत भी आक्रामक रूप से जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2 नवंबर, 2021 को, पीएम मोदी ने 2070 तक देश के उत्सर्जन को शुद्ध–शून्य करने का संकल्प लिया, भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य जहां जीवाश्म ईंधन अभी भी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। हालाँकि, पीएम मोदी ने बार–बार उपलब्ध ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के दोहन और देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर जोर दिया है। 2014 से पहले भारत को एक अनिच्छुक क्षेत्रीय शक्ति माना जाता था जिसे उसके भ्रष्ट शासन मॉडल माना जाता था। लेकिन 2014 के बाद, दुनिया भारत की अंतर्निहित क्षमता की प्रशंसा करने और पहचानने में लगी है।

पड़ोसी देशों, विशेषकर पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस

मोदी सरकार की विदेश नीति का एक आधार पड़ोसी देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक से अधिक मौकों पर पाकिस्तान की परमाणु धौंस का पर्दाफाश किया है, जिससे पाकिस्तान के दो शक्ति केंद्रों इस्लामाबाद और रावलपिंडी को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत आतंक के प्रति उतना उदार नहीं होगा। जितने हमले यूपीए के दिनों में हुए थे। [10]

जबकि यूपीए–द्वितीय ने 26/11 के नृशंस मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान को निशाने पर लेने से परहेज करने में चौंकाने वाली कायरता का प्रदर्शन किया, पीएम मोदी ने 2016 में उरी आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को भेजने के लिए जिम्मेदार आतंकी लॉन्चपैड के खिलाफ दुस्साहसी सर्जिकल स्ट्राइक को अधिकृत किया। आतंकी हमले के बाद, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर एक जवाबी कार्रवाई शुरू की, और आतंकी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया, जिससे भारत में आतंकवादी हमलों से निपटने और पाकिस्तान द्वारा विस्तार से अपनी नीति में मौलिक बदलाव का संकेत मिला। [11]

भारत की पश्चिमी सीमाओं पर हमला करने से पहले, भारतीय सशस्त्र बलों ने कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए म्यांमार के घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए इसी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। वर्षों बाद, 2019 में, मोदी सरकार ने पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में जैश–ए–मोहम्मद द्वारा संचालित एक आतंकी शिविर का सफाया करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर, बालाकोट में एक अभूतपूर्व हवाई हमले को मंजूरी दी। [12]

मोदी सरकार ने विवादित अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को एक अलग दर्जा दिया और भारत के संघ के साथ राज्य का अधिक एकीकरण किया। दो केंद्र शासित प्रदेश–जम्मू और कश्मीर और लद्दाख–तत्कालीन राज्य से अलग किए गए थे, अलगाववादी प्रवृत्तियों वाले स्वयंभू स्थानीय राजनेताओं से सीमावर्ती राज्य का नियंत्रण छीन लिया और इसे केंद्र में स्थानांतरित कर दिया।[13]

पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में प्रचारकों ने इस कदम पर छटपटाहट की, लेकिन मोदी सरकार अपने रुख पर अड़ी रही कि जम्मू–कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। विशेष रूप से, अनुच्छेद 370 के अमान्य होने से घाटी में आतंकी फंडिंग पर झटका लगा, नतीजतन, धारा 370 के निरस्त होने के बाद पथराव और आतंकी हमलों की घटनाओं में भारी कमी आई।

लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना कश्मीर के मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति से प्रस्थान का प्रदर्शन करता है। पिछली सरकारों ने कश्मीर में पाकिस्तान और अलगाववादियों को एक स्थान दिया हुआ था, जिससे उन्हें अपने नापाक मंसूबों को जारी रखने का मौका मिलता था। हालाँकि, धारा 370 को हटाकर भारत ने न केवल पाकिस्तान के साथ अपनी आगे की चर्चाओं की शर्तों को बदल दिया, बल्कि दुनिया को यह संकेत भी दिया कि वह कश्मीर के चोरी हुए हिस्सों को वापस लाने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ है।

संकट में फंसे भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

मोदी सरकार पारस्परिक विकास के लिए विदेशी देशों के साथ स्थायी संबंध बनाना अपनी प्राथमिकता में रखती है या वर्तमान विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अतिरिक्त विदेश में संकट में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित

करना भी वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। स्व. सुषमा स्वराज ने इस नीति के तहत विदेशों में फंसे कई भारतियों को ना केवल बचाया बल्कि उनकी स्वदेश वापसी में भी सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अतिरक्त भारत सरकार भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उभर रहे जटिल संकटों को दूर करने में काफी कुशल और सक्रिय रही है।[14]

मोदी सरकार ने दूर स्थानों में फंसे लोगों को निकालने में असाधारण साहस दिखाया। पिछले साल, भारत ने तालिबान द्वारा अमेरिका समर्थित सरकार को उखाड़ फेंकने और देश पर नियंत्रण करने के बाद अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक निकासी योजना शुरू की।[15]

2019 में, नागरिक अशांति के कारण जमीन पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच, भारत ने लीबिया में फंसे सीआरपीएफ के एक दल को सफलतापूर्वक बाहर निकाला था। इससे पहले, भारत सरकार ने 2015 में युद्धग्रस्त यमन से 4,500 से अधिक भारतीयों और 960 विदेशियों को बचाया था। भारत ने 2014 में संघर्षग्रस्त इराक में आईएसआईएस की कैद से 46 नर्सों को भी बचाया था। [16]

भारत और चीनः क्षेत्रीय अखंडता और सीमा सुरक्षा की रक्षा पर भारत का अटल रुख

पीएम मोदी के नेतृत्व में, भारत बढ़ते चीनी आक्रामकता के सामने अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर जोर देने के लिए आगे बढ़ा है। जबकि पिछली सरकारों ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को चीनी हस्तक्षेप और विस्तार की नीति से देश बचाने के लिए ना के बराबर विरोध दर्ज किया अथवा मौन बने रहे, चीन को अब भारत से कड़ा प्रतिरोध देखने को मिलता है और इसलिए बौखलाया हुआ है। [17]

उदाहरणार्थ जून 2017 में, भारतीय सशस्त्र बलों और चीनी सैनिकों के मध्य डोकलाम सीमा पर चीन द्वारा सड़क निर्माण को लेकर एक तनावपूर्ण माहौल बना ऐसी परिस्थिति में भारत ने चीनी निर्माण का तीव्र विरोध किया और भारतीय सीमा के क्षेत्रों पर चीनी दबाव को कम करने का प्रयास किया। इस कार्यवाही के तहत भारत ने ऑपरेशन जुनिपर को शुरू किया जिसमें भारत ने हथियारों से लैस 270 सैनिकों को तैनात किया और चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोकने के लिए प्रयास किए। कई हफ्तों चली वार्ता और कूटनीति के सहारे 28 अगस्त 2017 को भारत और चीन दोनों राष्ट्रों ने घोषणा करि के उन्होंने डोकलाम से अपने सभी सैनिकों को हटा लिया है। अंततः भारत की कूटनीतिक विजय हुई और डोकलाम गतिरोध का अंत हुआ। [18]

सन 2020 में पूर्वी लद्दाख के एरिया में भारतीय सैनिक एवं चीनी सैनिक एक महीने तक आमने सामने खड़े थे। भारत उस समय कोरोना वायरस से निबटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा था जिस वजह से चीन की सरकार को लगा के भारत का ध्यान सीमावर्ती क्षेत्रों पर उतना नहीं होगा और चीन ने अपनी सेना उन सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजी। [19]

15 जून, 2020 को, लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच रात में शून्य से नीचे तापमान में कड़ा संघर्ष हुआ, जिसने दोनों देशों के मध्य सीमा तनाव को बढ़ा दिया। दोनों देशों के सैनिको के मध्य झड़प हुई जिसमें 35–40 चीनी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालाँकि चीन इस तथ्य को नकारता आया है। इस घटना के बाद चीन को ये एहसास हो चूका है के भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता को प्रमुख महत्व देता है और सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी भूमि को बचाने के लिए युद्ध अथवा सैन्य साधनों का उपयोग करने से हिचकिचाएगा नहीं। [20]

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में भारत की सामरिक अस्पष्टता

हाल ही में हुए रूस–यूक्रेन युद्ध में भारत ने कूटनीतिक चुप्पी साधी हुई है। इस युद्ध में भारत ने पश्चिम से मान्यता प्राप्त करने की इच्छा और उनके नजदीक जाने से ज्यादा राष्ट्र हित को वरीयता दी। भारत की इस नीति से देश–विदेश के लिबरल और मार्क्सवादी खेमे में खलबली मची हुई है, ये राष्ट्र हित से इतर इस बात के कारण विरोश कर रहे हैं के भारत की विदेश नीति रूस–यूक्रेन युद्ध के समय पश्चिम राष्ट्रों के साथ क्यों नहीं है? भारत ने स्पष्ट किया है के इस मुद्दे पर उसने रूस का विरोध नहीं किया क्योंकि रूस भारत का सबसे पुराना मित्र और सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार हैं। [21]

भारत ने अपने लगभग सभी आधुनिक हथियार रूस से खरीदे हैं। भारत के लगभग 85ः हथियार रूस से आयातित हैं। इसके अतिरिक्त, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मत है कि 2019–20 में खरीदे गए विभिन्न प्रकार के रूसी हथियारों के कारण भारत आने वाले पांच वर्षों में रूसी हथियारों के निर्यात में वृद्धि करेगा। [22]

रूस के खिलाफ पश्चिम एवं यूरोपियन राष्ट्रों द्वारा थोपे गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से दोगुने से अधिक कच्चे तेल की खरीद की है, रूस ने भी बाजार भाव से कम कीमतों पर कच्चे तेल का भारत को निर्यात किया है। इससे ना केवल भारत पर कच्चे तेल खरीदने का अतिरिक्त दबाव कम हुआ बल्कि भारत को कम कीमतों पर तेल मिलने से ईंधन की आपूर्ति सुलभ हुई है। कूटनीतिक रूप से राष्ट्रहित और मित्रता दोनों क्षेत्रों में ये सबसे प्रभावशाली कदम है।[23] रूस–यूक्रेन संकट में पश्चिमी और यूरोपियन राष्ट्रों की बातों को नकारने और तटस्थता बनाए रखने के साथ सरकार ने दिखाया के उसकी विदेश नीति राष्ट्र के हित में निहित है ना कि पश्चिम द्वारा प्रचारित नैतिकता के मानकों का पालन करने में नहीं।

References

1. "Election Results 2014: 5 Factors that Helped BJP and Narendra Modi Win the Election," *NDTV Election*. (May 16. 2014). Accessed Via: https://www.ndtv.com/cheat-sheet/election-results-2014-5-factors-that-helped-bjp-and-narendra-modi-win-the-election-562309. Dated. 12/10/2020. See also, Press Trust of India (2013), "Corruption, inflation to be 2014 election issues: BJP," *Business Standard* (February. 18). Accessed Via: https://www.business-standard.com/article/pti-stories/corruption-inflation-to-be-2014-election-issues-bjp-113021800930_1.html. Dated. 12/10/2020.
2. Ibid.
3. Kumar Umar Shakti Shekhar (2019), "10 reasons why Narendra Modi-led BJP won Lok Sabha elections 2019," *The Times of India* (May.23). Accessed Via: https://timesofindia.indiatimes.com/india/10-reasons-

why-narendra-modi-led-bjp-won-lok-sabha-elections-2019/articleshow/69466610.cms. 16/12/2020.see also, Sen, Ronojoy, "Indian Elections 2019: Why the BJP Won Big," *Institute of South Asian Studies.* No,2019:666(June.1):5-6. Accessed Via: https://www.isas.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/06/ISAS-Briefs-No.-666.pdf. Dated. 19/12/2020.

4. Aldo D Abitol. "Causes of the 1962 Sino-Indian War: A Systems Level Approach," Josef Korbel Journal of Advanced International Studies 1 (Summer), 2009, 74-88. Accessed Via: https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=advancedintlstudies. Dated. 22/12/2022.
5. Man Aman Singh Chhina. "Former IAF chief says Balakot strike was message that Pak will pay price for attacks in India," The Indian Express. (December. 15), 2019. Accessed Via: https://indianexpress.com/article/india/balakot-strike-was-message-to-pak-that-it-will-pay-a-price-for-terror-attacks-in-india-former-iaf-chief-6167690/, Dated. 9/1/2020.
6. W.P.S. Sidhu Vikram Singh Mehta. "Modi's Foreign Policy @365: Course Correction," *IndiaGov2015*. (July), 2015. Accessed Via: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2015/05/modi365_final-book.pdf. Dated. 22/12/2020. See also, Pradhan, SD (2022), "Key Features of Indian Foreign Policy under PM Modi," The Times of India (January.9). Accessed Via: https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/ChanakyaCode/key-features-of-indian-foreign-policy-under-pm-modi/. Dated. 16/1/2022.
7. Ibid.
8. PTI. "India playing 'pharmacy of the world' role during COVID-19 crisis: SCO Secretary-General," (June. 20), 2020. Accessed Via: https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/pharmaceuticals/india-playing-pharmacy-of-the-world-role-during-covid-19-crisis-sco-secretary-general/articleshow/76492428.cms?from=mdr. Dated. 11/7/2020.
9. McGrath. Matt. "India's Bold Step," (November.2), 2021. Accessed Via: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59125143. Dated. 16/11/2021.
10. Sahoo Prasanta. "Narendra Modi's Anti-Terrorism Strategy And India's Islamic Neighbours," World Affairs: The Journal of International Issues. Vol. 21, No. 1 (SPRING (January-March), 2017, 122-135.
11. Ibid.
12. Man Aman Singh Chhina. Opp.Cite, 2019.
13. Surana, Anshita, "Abrogation of Article 35A And Article 370," *GETLegal India*. Accessed Via: https://getlegalindia.com/article-35a/. 16/11/2021.
14. "Remembering Sushma Swaraj: An empathetic leader who often rescued Indians stuck overseas," *The Economic Times*, (August.7. 2019). Accessed Via: https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/remembering-sushma-swaraj-an-empathetic-leader-who-often-rescued-indians-stuck-overseas/articleshow/70563860.cms?from=mdr. Dated. 16/4/2020.
15. "India's evacuation mission from Afghanistan named 'Operation Devi Shakti," *The Hindu* (August. 24. 2021). Accessed Via: https://www.thehindu.com/news/national/indias-evacuation-mission-from-afghanistan-named-operation-devi-shakti/article36075754.ece. Dated. 11/9/2021.
16. "Operation Ganga To Vande Bharat: India's Biggest Evacuation Missions In Recent Past," *Outlook* (March.2. 2022). Accessed Via: https://www.outlookindia.com/national/operation-ganga-to-vande-bharat-india-s-biggest-evacuation-missions-in-recent-past--news-184730. Dated. 1/5/2022.
17. Roy-Chaudhury, Rahul. "Modi's approach to China and Pakistan," European Council on Foreign Relations (October), 2020. Accessed Via: https://ecfr.eu/special/what_does_india_think/analysis/modis_approach_to_india_and_pakistan. 11/9/2021.
18. Joseph, Josy (2018), "What is the Doklam issue all about? *The Hindu* (January 27). Accessed Via: https://www.thehindu.com/news/national/what-is-the-doklam-issue-all-about/article22536937.ece. Dated. 13/9/2021.
19. Snehesh Alex Philip. "Chinese troops challenge India at multiple locations in eastern Ladakh, standoff continues," *The Print* (May. 24), 2020. Accessed Via: https://theprint.in/defence/chinese-troops-challenge-india-at-multiple-locations-in-eastern-ladakh-standoff-continues/428304/. Dated. 16/9/2021.
20. Ghosh Deepshikha. "At Talks, China Confirms Commanding Officer Was Killed In Ladakh," *NDTV* (June. 22). Accessed Via: https://www.ndtv.com/india-news/chinese-army-confirms-their-commanding-officer-was-killed-in-ladakh-face-off-during-military-level-talks-in-galwan-sources-2250280. Dated. 18/9/2020. See also, "China suffered 43 casualties during face-off with India in Ladakh," (June. 16). 2020. Accessed Via: https://www.indiatoday.in/india/story/india-china-face-off-ladakh-lac-chinese-casualties-pla-1689714-2020-06-16. Dated. 20/9/2020.
21. Shah, Bipin. "India's stand on Ukraine explained," The Times of India. (June. 11). Accessed Via: https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/bipin-shah/indias-stand-on-ukraine-explained/. Dated. 7/6/2022. See also, "Neutrality and abstention: On India's stand in the Russia-Ukraine conflict," The Hindu. (October.6.), 2022. Accessed Via: https://www.thehindu.com/opinion/editorial/neutrality-and-abstention-the-hindu-editorial-on-indias-stand-in-the-russia-ukraine-conflict/article65972267.ece. Dated. 12/10/2022.
22. Ibid.
23. Ibid.